

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 19-06-2026

विषय सूची

भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाली पाँच प्रमुख मौसमीय प्रणालियाँ

भारत में औषधि क्षेत्र का नियामकीय पर्यवेक्षण

क्या भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती स्नातक संख्या को समाहित करने में सक्षम है?

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की राज्य वित्त रिपोर्ट

संक्षिप्त समाचार

रंग समुदाय

एनपीसीआई द्वारा डूनिक्स प्लेटफॉर्म का अनावरण

मिशन शक्ति के अंतर्गत SHe-Box 2.0 पोर्टल

डार्क वेब

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY)

QS रैंकिंग

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0

अभ्यास खान केस्ट 2026

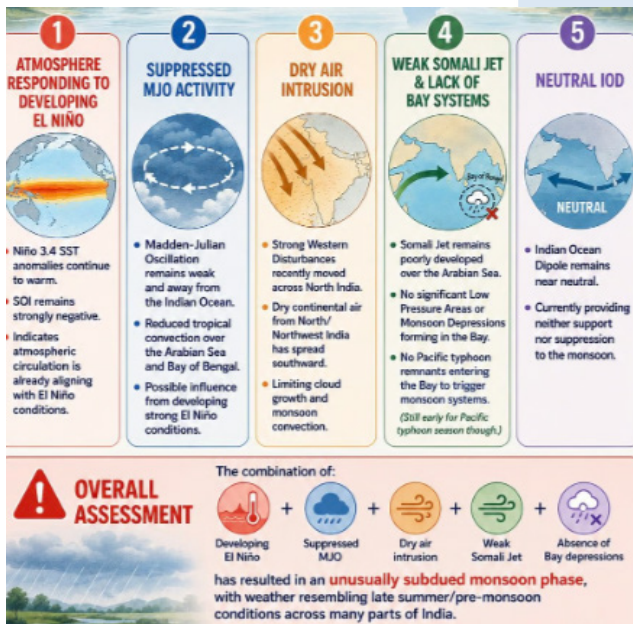
भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाली पाँच प्रमुख मौसमीय प्रणालियाँ

संदर्भ

- भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून आगामी एक सप्ताह तक कमजोर अथवा लगभग स्थिर स्थिति में रह सकता है, क्योंकि एक ही समय में वर्षा को दबाने वाले पाँच प्रमुख कारक सक्रिय हैं।

परिचय

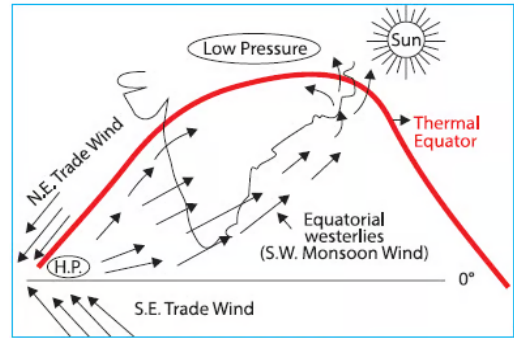
- 1 जून से 17 जून के बीच भारत में देशव्यापी वर्षा में 38 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, जबकि मध्य भारत में सर्वाधिक 62 प्रतिशत वर्षा घाटा देखा गया है।
- वर्षा को प्रभावित करने वाले पाँच प्रमुख अवरोधक कारक निम्नलिखित हैं—
 - एल नीनो की विकसित होती परिस्थितियाँ
 - मैडेन-जूलियन दोलन (MJO) की कमजोर सक्रियता
 - शुष्क पछुआ (पश्चिमी) पवनें
 - कमजोर सोमाली जेट
 - हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) की तटस्थ अवस्था



दक्षिण-पश्चिम मानसून

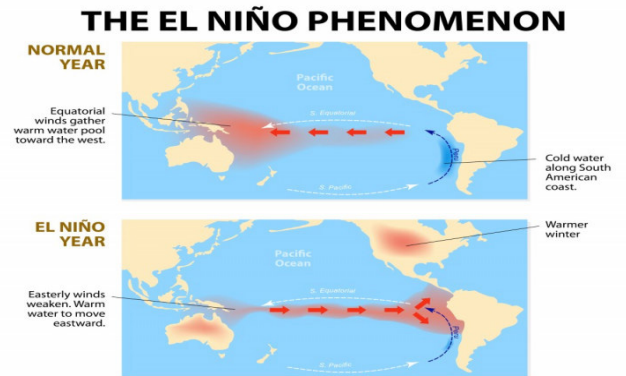
- आगमन एवं वापसी: भारत में मानसून ऋतु सामान्यतः जून के प्रारम्भ में आरम्भ होकर सितंबर तक रहती है।

- मानसून का आगमन दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी पवनों के प्रवेश से चिह्नित होता है, जो हिंद महासागर से आर्द्रता युक्त वायु लेकर आती हैं।
- मानसून की वापसी अथवा प्रत्यावर्तन सामान्यतः अक्टूबर माह से प्रारम्भ होता है।
- अक्टूबर से दिसंबर के बीच सक्रिय रहने वाला उत्तर-पूर्व मानसून दक्षिण भारत के कुछ भागों में वर्षा प्रदान करता है।



मानसून को प्रभावित करने वाले कारक

- **एल नीनो** : स्पेनिश भाषा में एल नीनो का अर्थ “छोटा बालक” होता है। यह एक जलवायु संबंधी परिघटना है, जिसकी विशेषता मध्य एवं पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागर में समुद्र सतह के तापमान में समय-समय पर होने वाली असामान्य वृद्धि है।
- एल नीनो की स्थिति में व्यापारिक पवनें कमजोर पड़ जाती हैं।
- इसके परिणामस्वरूप गर्म जल पूर्व दिशा की ओर, अर्थात् अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर विस्थापित हो जाता है, जबकि अपेक्षाकृत ठंडा जल एशिया की ओर प्रवाहित होता है।

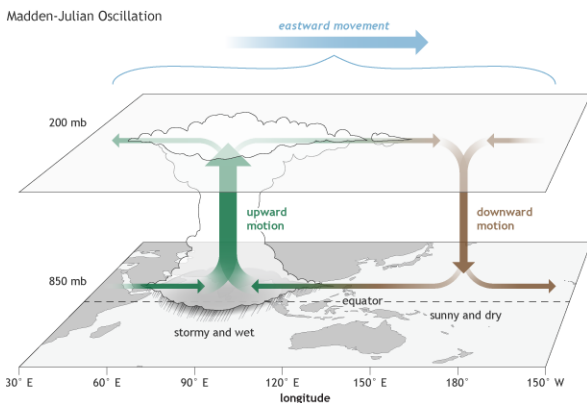


- मौसम प्रतिरूपों पर एल नीनो का प्रभाव: वैश्विक तापमान में वृद्धि करता है।

- मानसून को कमजोर बनाता है।
- वनाग्नि की संभावनाएँ बढ़ाता है।
- चक्रवातों, हरिकेनों तथा अन्य चरम मौसमीय घटनाओं को प्रेरित करता है, विशेषकर प्रशांत एवं अटलांटिक महासागरों में।

मैडेन-जूलियन दोलन (MJO)

- MJO पवनों, बादलों तथा वायुदाब का एक गतिशील तंत्र है, जो विषुवत रेखा के चारों ओर परिभ्रमण करते हुए वर्षा उत्पन्न करता है।
- इसकी खोज वर्ष 1971 में रोलैंड मैडेन और पॉल जूलियन द्वारा की गई थी।
- यह तंत्र पूर्व दिशा की ओर लगभग 4-8 मीटर प्रति सेकंड की गति से संचालित होता है तथा सामान्यतः 30-60 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है, हालांकि कभी-कभी इसमें 90 दिन तक लग सकते हैं।
- गतिशीलता के दौरान MJO की प्रबल सक्रियता पृथ्वी को सामान्यतः दो भागों में विभाजित कर देती है—
 - एक भाग, जहाँ यह सक्रिय अवस्था में रहकर वर्षा को प्रोत्साहन देता है।
 - दूसरा भाग, जहाँ यह वर्षा को दबाता है।
- **सक्रिय MJO चरण के प्रभाव:** सक्रिय MJO चरण के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा होती है, जिसका कारण है—
 - बादलों का अधिक निर्माण
 - संवहन में वृद्धि
 - चक्रवाती गतिविधियों में वृद्धि



पश्चिमी विक्षोभ

- पश्चिमी विक्षोभ (WD) एक बहिर्उष्णकटिबंधीय मौसमीय प्रणाली है, जिसकी उत्पत्ति भारत के बाहर होती है तथा जो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में वर्षा, हिमपात और तूफानी परिस्थितियाँ उत्पन्न करती है।
- **उत्पत्ति एवं निर्माण:** पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति सामान्यतः निम्न क्षेत्रों में होती है—
 - भूमध्यसागरीय क्षेत्र
 - काला सागर क्षेत्र
 - कैस्पियन सागर क्षेत्र
- इनका निर्माण तब होता है जब ठंडी ध्रुवीय वायु उष्ण एवं आर्द्र वायु के संपर्क में आती है, जिससे निम्न दाब प्रणालियाँ विकसित होती हैं।
- ये प्रणालियाँ ऊपरी वायुमंडल में प्रवाहित होने वाली पछुआ पवनों, विशेषकर उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट धारा के माध्यम से पूर्व दिशा की ओर अग्रसर होती हैं।

हिंद महासागर द्विध्रुव

- वर्ष 1999 में जापान के वैज्ञानिक एन. एच. साजी ने हिंद महासागर में ENSO जैसी एक परिघटना की खोज की, जिसे हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) नाम दिया गया।
- ENSO की भाँति IOD की भी तीन अवस्थाएँ होती हैं—
 - सकारात्मक
 - नकारात्मक
 - तटस्थ
- **सकारात्मक IOD अवस्था:** सकारात्मक अवस्था में पश्चिमी हिंद महासागर का समुद्री सतह तापमान अपेक्षाकृत अधिक गर्म होता है, जिससे मानसूनी पवनों को अतिरिक्त ऊर्जा एवं बल प्राप्त होता है।
- **नकारात्मक एवं तटस्थ अवस्था:** नकारात्मक अवस्था में इसके विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं।
 - तटस्थ अवस्था में समुद्री सतह तापमान का कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं पाया जाता।

सोमाली जेट

- सोमाली जेट एक तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली अंतर-गोलाद्धीय एवं विषुवत रेखा को पार करने वाली वायु धारा है।
 - इसकी उत्पत्ति दक्षिणी गोलाद्ध में मॉरीशस तथा मेडागास्कर के उत्तरी भाग के निकट होती है।
 - यह वायु धारा विषुवत रेखा को पार करके अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ-साथ—
 - केन्या
 - इथियोपिया
 - सोमालिया से होकर प्रवाहित होती है।
 - मई माह के दौरान यह अरब सागर में प्रवेश करती है तथा जून तक भारत के पश्चिमी तट तक पहुँच जाती है।
 - **मानसून में भूमिका:** अपने प्रवाह के दौरान सोमाली जेट महासागर से बड़ी मात्रा में आर्द्रता (जलवाष्प) ग्रहण करती है।
 - जब सोमाली जेट अधिक शक्तिशाली होती है, तब यह प्रायद्वीपीय भारत में अधिक तीव्र, व्यापक एवं विश्वसनीय मानसूनी वर्षा लाती है।

Source: DTE

भारत में औषधि क्षेत्र का नियामकीय पर्यवेक्षण

संदर्भ

- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 की अनुसूची K से सिरप शब्द को हटा दिया है। इसके परिणामस्वरूप अब खाँसी की दवाओं (कफ सिरप) की बिक्री केवल चिकित्सकीय पर्चे के आधार पर ही की जा सकेगी।

पृष्ठभूमि

- यह कदम वर्ष 2022 के बाद विभिन्न देशों में बच्चों सहित अनेक लोगों की मृत्यु की घटनाओं के मद्देनजर उठाया गया है, जिनका कारण औद्योगिक विलायकों से मिलावटी कफ सिरप पाए गए थे।
- इस निर्णय ने औषधि नियमन, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन तथा वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था में भारत की

भूमिका से संबंधित अनेक चिंताओं को पुनः उजागर किया है।

भारत का औषधि क्षेत्र

- भारत को विश्व की “फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड” कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सस्ती कीमतों और गुणवत्तापूर्ण औषधियों का अद्वितीय संयोजन उपलब्ध है, जिसने भारतीय दवाओं को वैश्विक बाजारों में व्यापक स्वीकृति दिलाई है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर संयुक्त राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (USFDA) द्वारा अनुमोदित विनिर्माण संयंत्रों की सर्वाधिक संख्या भारत में स्थित है, जो भारतीय औषधियों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा के प्रति अंतरराष्ट्रीय विश्वास को सुदृढ़ करती है।
 - भारत में लगभग 500 सक्रिय औषधीय संघटक निर्माता कार्यरत हैं, जो वैश्विक API उद्योग का लगभग 8 प्रतिशत योगदान करते हैं।



भारत के औषधि नियामकीय तंत्र से संबंधित प्रमुख चिंताएँ

- **विनिर्माण गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ:** औषधियों में संदूषण तथा गुणवत्ता संबंधी कमियों की घटनाएँ समय-समय पर सामने आती रही हैं, जो विनिर्माण मानकों के अनुपालन में विद्यमान कमजोरियों को दर्शाती हैं।
- **खंडित नियामकीय पर्यवेक्षण:** विभिन्न नियामकीय प्राधिकरणों तथा उनके भिन्न-भिन्न प्रवर्तन मानकों के कारण निगरानी एवं नियंत्रण में असंगतियाँ उत्पन्न होती हैं।
- **बिना चिकित्सकीय परामर्श के औषधि उपयोग की प्रवृत्ति:** भारत में स्व-औषधोपचार की व्यापक प्रवृत्ति दवाओं के अविवेकपूर्ण एवं असुरक्षित उपयोग के जोखिम को बढ़ाती है।

- **नियामकीय क्षमता संबंधी सीमाएँ:** भारत में औषधि नियमन संघ एवं राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी है।
 - कई राज्यों के औषधि नियंत्रण विभाग निम्नलिखित संसाधनों की कमी का सामना कर रहे हैं—
 - औषधि निरीक्षक
 - परीक्षण प्रयोगशालाएँ
 - तकनीकी विशेषज्ञ एवं कार्मिक
 - **भारतीय औषधसंग्रह आयोग (IPC):** भारतीय औषधसंग्रह आयोग भारतीय औषधसंग्रह के नियमित प्रकाशन की निगरानी करता है, जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत औषधि मानकों का आधिकारिक संकलन है।
 - **भारतीय औषधसंग्रह की भूमिका:** यह भारत में विपणन की जाने वाली औषधियों के लिए निम्नलिखित मानक निर्धारित करता है—
 - पहचान
 - शुद्धता
 - सामर्थ्य/प्रभावकारिता
 - **राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण (SLAs):** औषधियों के विनिर्माण, बिक्री एवं वितरण पर नियामकीय नियंत्रण राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों के माध्यम से लाइसेंसिंग एवं निरीक्षण प्रणाली द्वारा किया जाता है।
 - इसके विपरीत, देश में आयातित औषधियों पर नियामकीय नियंत्रण केंद्रीय सरकार द्वारा CDSCO के माध्यम से किया जाता है।
 - **SHRESTH पहल:** स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स एक अभिनव राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य पारदर्शी एवं डेटा-आधारित ढाँचे के माध्यम से राज्य स्तरीय औषधि नियामकीय प्रणालियों का मूल्यांकन एवं सुदृढ़ीकरण करना है।
- भारत में औषधियों का विनियमन**
- **केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन:** केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, जिसका नेतृत्व भारतीय औषधि महानियंत्रक करते हैं, देश में विपणन की जाने वाली औषधियों की गुणवत्ता के विनियमन हेतु केंद्रीय प्राधिकरण है।
 - यह संस्था औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत कार्य करती है।
 - देश में औषधियों, प्रसाधनों तथा चिकित्सा उपकरणों के आयात, विनिर्माण, वितरण एवं बिक्री का विनियमन निम्नलिखित विधिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत किया जाता है—
 - औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940
 - औषधि नियम, 1945
 - चिकित्सा उपकरण नियम, 2017
 - नवीन औषधि एवं नैदानिक परीक्षण नियम, 2019
 - प्रसाधन सामग्री नियम, 2020
 - **राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण:** राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण को औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के अंतर्गत औषधियों की कीमतें निर्धारित एवं संशोधित करने का दायित्व सौंपा गया है।
 - **मुख्य कार्य:**
 - औषधियों की कीमतों का निर्धारण एवं संशोधन
 - मूल्य नियंत्रण आदेशों के अनुपालन की निगरानी
 - आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना
 - औषधि नीति संबंधी सलाह प्रदान करना
 - **आगे की राह**
 - गुणवत्ता नियंत्रण को केवल अंतिम उत्पाद के परीक्षण तक सीमित रखने के बजाय संपूर्ण विनिर्माण प्रक्रिया में समाहित किया जाना चाहिए।
 - निरीक्षण रिपोर्टों तथा नियामकीय कार्रवाई से संबंधित निष्कर्षों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
 - नियामकीय पर्यवेक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित आधुनिक तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए—
 - कृत्रिम बुद्धिमत्ता
 - डेटा विश्लेषण
 - डिजिटल ट्रैकिंग एवं निगरानी प्रणाली

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची K

- अनुसूची K में उन विशिष्ट औषधियों की सूची सम्मिलित है जिन्हें निर्धारित शर्तों के अधीन औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के कुछ प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है
- इसका उद्देश्य उन औषधियों की बिक्री एवं वितरण को सुगम बनाना है, जिनके लिए कठोर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को अनिवार्य नहीं माना जाता।

Source: TH

क्या भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती स्नातक संख्या को समाहित करने में सक्षम है?

संदर्भ

- भारत में उच्च शिक्षा में नामांकन 2014-15 के 3.42 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 4.46 करोड़ हो गया है, फिर भी लगभग प्रत्येक तीन स्नातकों में से एक बेरोजगार है। इससे एक मूलभूत प्रश्न उठता है कि क्या भारत अपनी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादक रूप से समाहित किए जा सकने वाले स्नातकों से अधिक संख्या में स्नातक तैयार कर रहा है।

परिचय

- विगत एक दशक में हजारों नए महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है, जो प्रतिवर्ष लाखों स्नातक तैयार कर रहे हैं।

Institution	2014	2025	Growth
IITs	16	23	+44%
IIMs	13	22	+69%
AIIMS	7	20	+186%
IIITs	9	25	+178%
IISERs	5	7	+40%
Universities	~ 760	~1,330	+ 75%
Colleges	~38,500	~52,000	+35%

Source: Ministry of Education

- उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2014-15 के 3.42 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 4.46 करोड़ हो गया है।

उच्च शिक्षा प्राप्त स्नातकों के समक्ष चुनौतियाँ

- **रोजगार सृजन में अंतराल** : केवल इंजीनियरिंग क्षेत्र में ही विगत कुछ वर्षों में स्नातकों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है, जबकि रोजगार सृजन उसी गति से नहीं बढ़ पाया है।
- **आईटी क्षेत्र में भर्ती की धीमी गति**: पूर्व में आईटी सेवा क्षेत्र इंजीनियरिंग स्नातकों का प्रमुख नियोक्ता था।
 - वर्तमान में आईटी सेवा कंपनियों द्वारा भर्ती की गति काफी धीमी हो गई है तथा नए अवसर इतनी तीव्रता से नहीं बढ़ रहे हैं कि श्रम बाजार में प्रवेश करने वाले बढ़ते हुए स्नातकों को समाहित कर सकें।
- **पूंजी-प्रधान निवेश**: सेमीकंडक्टर, उन्नत विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में हाल के निवेश श्रम-प्रधान होने के बजाय पूंजी-प्रधान हैं।
 - अतः बड़े निवेश संबंधी घोषणाएँ स्नातकों के लिए रोजगार सृजन में समानुपाती वृद्धि नहीं करती हैं। (आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25)
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का आगमन** : कंपनियों को ऐसे स्नातकों की आवश्यकता है जो एआई प्रणालियों के साथ कार्य कर सकें, एआई द्वारा उत्पन्न परिणामों का सत्यापन कर सकें तथा प्रौद्योगिकी की सहायता से जटिल समस्याओं का समाधान कर सकें।
 - विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रमों को तत्काल पुनः डिजाइन नहीं कर सकते तथा विद्यार्थी भी तुरंत नई दक्षताएँ अर्जित नहीं कर सकते।
- **विनिर्माण क्षेत्र में स्वचालन**: विनिर्माण क्षेत्र भी स्वचालन, रोबोटिक्स और इंडस्ट्री 4.0 प्रणालियों के कारण तीव्रता से परिवर्तित हो रहा है।
 - ऐतिहासिक रूप से बड़ी संख्या में इंजीनियर कारखानों में पर्यवेक्षी और परिचालन भूमिकाओं में कार्यरत थे, किंतु इनमें से अनेक कार्य अब स्वचालित हो चुके हैं।
 - परिणामस्वरूप, विनिर्माण क्षेत्र द्वारा उत्पन्न इंजीनियरिंग नौकरियों की संख्या अपेक्षित गति से नहीं बढ़ रही है।

सरकारी पहलें

- **राष्ट्रीय युवा नीति 2014:** राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 ने 15–29 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को युवा के रूप में परिभाषित किया तथा शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, स्वास्थ्य, खेल, सामाजिक सहभागिता एवं सशक्तिकरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की।
 - हाल ही में प्रस्तावित राष्ट्रीय युवा नीति 2025 ढाँचा भविष्य-उन्मुख कौशल, उद्यमिता, नेतृत्व, नागरिक सहभागिता, डिजिटल भागीदारी तथा सतत विकास जैसी उभरती प्राथमिकताओं पर विशेष बल देता है।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 अनुभवात्मक तथा बहुविषयक शिक्षण को प्रोत्साहित करती है।
- **राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क:** 170 विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाया गया यह ढाँचा विद्यार्थियों को शैक्षणिक, कौशल-आधारित तथा अनुभवात्मक शिक्षण के माध्यम से अर्जित क्रेडिट संचित करने की सुविधा प्रदान करता है।
- **ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (APAAR ID):** यह विद्यार्थियों की संपूर्ण शैक्षणिक यात्रा के दौरान अर्जित शैक्षणिक एवं कौशल-आधारित क्रेडिट का डिजिटल संकलन करता है।
- **स्वयं (SWAYAM):** SWAYAM पर 18,580 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।
 - इस मंच पर 6.1 करोड़ से अधिक नामांकन तथा 53.7 लाख प्रमाणन दर्ज किए गए हैं।
- **SWAYAM PRABHA, PM e-VIDYA एवं DIKSHA:** इन पहलों ने टेलीविजन, रेडियो, डिजिटल सामग्री तथा ई-संसाधनों के माध्यम से शिक्षा की पहुँच को और अधिक व्यापक बनाया है।
- **अटल नवाचार मिशन :** इस मिशन के अंतर्गत 10,000 से अधिक अटल टिकरिंग लैब्स स्थापित की गई हैं।
 - इन प्रयोगशालाओं ने उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित 16 लाख से अधिक परियोजनाओं के विकास को समर्थन प्रदान किया है।
- **राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना:** यह योजना वर्ष 2016 में प्रारंभ की गई थी और वर्तमान में इसके दूसरे चरण NAPS 2.0 का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
 - यह प्रशिक्षुओं को आंशिक वजीफा सहायता प्रदान कर प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देती है।
 - “सीखते हुए कमाओ” तथा उद्योग-केंद्रित कौशल विकास के लिए प्रशिक्षुता एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।
- **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान :** आईटीआई भारत में दीर्घकालिक व्यावसायिक शिक्षा की आधारशिला हैं तथा उद्योगों को निरंतर कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराते हैं।
 - विगत 12 वर्षों में सरकार ने इनके व्यापक विस्तार और आधुनिकीकरण को सुनिश्चित किया है।
- **SOAR (कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तत्परता हेतु कौशल विकास), 2025:** वर्ष 2025 में प्रारंभ की गई यह पहल कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रति जागरूकता तथा आधारभूत एआई कौशल प्रदान करती है।
 - यह शिक्षकों को भी शिक्षण प्रक्रिया में एआई अवधारणाओं को समाहित करने हेतु सक्षम बनाती है।
 - कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए 15-15 घंटे के तीन मॉड्यूल उपलब्ध कराए गए हैं।
- **प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना , 2024:** यह एक प्रमुख परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच की दूरी को कम करना है।
 - इसके माध्यम से देशभर के युवाओं को संरचित एवं सवेतन इंटरशिप अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।
- **स्किल इंडिया डिजिटल हब , 2023:** यह कौशल विकास, रोजगार, प्रशिक्षुता तथा उद्यमिता के लिए एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना मंच के रूप में कार्य करता है।
 - यह शिक्षार्थियों, प्रशिक्षण प्रदाताओं, नियोक्ताओं तथा सरकारी कार्यक्रमों को एक ही डिजिटल मंच पर जोड़ता है।

आगे की राह

- भारत को अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाना होगा।
- उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच अधिक घनिष्ठ सहयोग स्थापित करना आवश्यक है।

- भारत को एक सशक्त उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना होगा, जो नवाचार को प्रोत्साहित करे तथा जोखिम लेने की संस्कृति को समर्थन प्रदान करे।
- भारत को डिजाइन, इंजीनियरिंग तथा उन्नत विनिर्माण के क्षेत्रों में स्वदेशी क्षमताओं का निरंतर विकास करना चाहिए।
- विशेष रूप से रक्षा और एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में व्यापक अवसर उपलब्ध हैं।
- मुख्य चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा, उद्योग और नीति—तीनों एक ही दिशा में समन्वित रूप से आगे बढ़ें।
- **राजस्व व्यय का प्रभुत्व:** कुल राज्य व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 83% से अधिक रहा।
 - सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय संयुक्त रूप से कुल व्यय का लगभग दो-तिहाई था, जो कल्याणकारी व्यय पर बढ़ते जोर को दर्शाता है।
- **सब्सिडी का क्षेत्रवार वितरण:** ऊर्जा सब्सिडी, विशेष रूप से विद्युत सब्सिडी, कुल सब्सिडी व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा रही।
 - विद्युत एवं सिंचाई सब्सिडी सहित कृषि सहायता भी राज्य व्यय का एक प्रमुख घटक बनी रही।

Source: TH

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की राज्य वित्त रिपोर्ट

संदर्भ

- हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की **राज्य वित्त रिपोर्ट 2024-25** ने भारत के राजकोषीय परिदृश्य में उभरती एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

CAG रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **सब्सिडी व्यय में वृद्धि:** वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्यों का सब्सिडी व्यय उनके राजस्व व्यय का 10.2% तक पहुँच गया, जबकि महामारी के बाद यह औसतन लगभग 8.5% था।
 - वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकारों ने सब्सिडी पर लगभग 4.4 लाख करोड़ रुपये व्यय किए, जो एक दशक पूर्व के स्तर की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है।
 - कर्नाटक में सब्सिडी का भार सर्वाधिक दर्ज किया गया, जहाँ कुल व्यय का 14.01% सब्सिडी पर व्यय हुआ।
- **सबसे अधिक सब्सिडी भार वाले राज्य:** कर्नाटक में सब्सिडी का भार सर्वाधिक रहा, जहाँ कुल व्यय का 14.01% सब्सिडी पर व्यय किया गया।
 - उच्च सब्सिडी व्यय वाले अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान शामिल हैं।

CAG द्वारा व्यक्त चिंताएँ

- **संकुचित होता राजकोषीय अवकाश :** राजस्व प्राप्तियों का एक बड़ा भाग अनिवार्य व्यय दायित्वों में व्यय हो रहा है, जिससे नई विकासात्मक पहलों के लिए सीमित संसाधन उपलब्ध रह जाते हैं।
- **पूँजीगत व्यय का प्रतिस्थापन:** सब्सिडी पर बढ़ता व्यय अवसंरचना, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश को सीमित करता है।
- **स्थिरता संबंधी जोखिम:** राजस्व में समानुपाती वृद्धि के बिना सब्सिडी कार्यक्रमों का निरंतर विस्तार राजकोषीय घाटे और ऋण स्तर में वृद्धि का कारण बनता है।

आगे की राह

- CAG ने राज्यों को कल्याणकारी व्यय और विकासात्मक व्यय के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया है।
- सब्सिडी कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए ताकि उनकी दक्षता, उचित लक्ष्यीकरण तथा राजकोषीय विवेकशीलता सुनिश्चित की जा सके।

Source: TOI

संक्षिप्त समाचार

रंग समुदाय

संदर्भ

- उत्तराखंड में रंग समुदाय ने ओम पर्वत के निकट शिवलिंग की स्थापना का विरोध किया। समुदाय ने इसका कारण अपनी प्रकृति-पूजा की परंपरा को बताया।

परिचय

- रंग एक स्वदेशी (आदिवासी) समुदाय है, जो मुख्यतः उत्तराखण्ड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र की सीमावर्ती घाटियों तथा नेपाल के कुछ भागों में निवास करता है। यह समुदाय अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं और प्रकृति-पूजा के लिए जाना जाता है।
- **मुख्य तथ्य:** यह समुदाय मुख्यतः **व्यास घाटी, दारमा घाटी तथा चौदास घाटी** में निवास करता है।
 - रंग समुदाय भगवान शिव की प्राकृतिक अभिव्यक्तियों को पूजनीय मानता है, जिनमें **ओम पर्वत** तथा **आदि कैलाश** जैसे पवित्र पर्वत शामिल हैं।

स्रोत: TH

एनपीसीआई द्वारा ड्रुनिक्स (Drunix) प्लेटफॉर्म का अनावरण

संदर्भ

- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने ड्रुनिक्स (Drunix) नामक एक ओपन-सोर्स ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य कंपनियों को टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म, डिजिटल परिसंपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र तथा बहु-संगठन नेटवर्क विकसित करने और उनका विस्तार करने में सहायता प्रदान करना है।

परिचय

- ड्रुनिक्स एक उच्च-प्रदर्शन वितरित लेजर प्लेटफॉर्म है, जिसे उद्यम-स्तरीय तथा सार्वजनिक अवसंरचना के व्यापक उपयोग के लिए विकसित किया गया है।
- यह प्लेटफॉर्म **हाइपरलेजर फैब्रिक** के उन्नत संस्करण पर आधारित है।
- हाइपरलेजर फैब्रिक एक ओपन-सोर्स एंटरप्राइज ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क है, जिसे **लिनक्स फाउंडेशन** के अंतर्गत विकसित किया गया है और जिसका व्यापक उपयोग अनुमति-आधारित ब्लॉकचेन अनुप्रयोगों में किया जाता है।

टोकनाइजेशन क्या है?

- टोकनाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी परिसंपत्ति अथवा स्वामित्व अधिकार को ब्लॉकचेन पर डिजिटल टोकन के रूप में परिवर्तित किया जाता है।

- इन परिसंपत्तियों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं—
 - वित्तीय प्रतिभूतियाँ
 - अचल संपत्ति
 - वस्तुएँ/कमोडिटीज
 - डिजिटल मुद्राएँ
 - पहचान संबंधी प्रमाण-पत्र

स्रोत: BS

मिशन शक्ति के अंतर्गत SHe-Box 2.0 पोर्टल

संदर्भ

- सरकार ने कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न संबंधी कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने में मिशन शक्ति के अंतर्गत SHe-Box 2.0 पोर्टल की भूमिका को रेखांकित किया है।

SHe-Box क्या है?

- **यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स(SHe-Box)** पोर्टल को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।
- इस पोर्टल को **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD)** द्वारा लॉन्च किया गया था।
- **SHe-Box 2.0** को वर्ष 2024 में प्रारंभ किया गया, जो एक सुरक्षित, गोपनीय तथा उपयोगकर्ता-अनुकूल मंच प्रदान करता है। यह महिलाओं को किसी भी प्रकार के कलंक या प्रतिशोध के भय के बिना शिकायत दर्ज कराने की सुविधा देता है।
 - यह संगठित, असंगठित, सार्वजनिक तथा निजी सभी क्षेत्रों की महिलाओं को शिकायत दर्ज करने एवं उसकी प्रगति को ट्रैक करने हेतु एकल-खिड़की सुविधा उपलब्ध कराता है।
 - यह पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी सहित **22 भाषाओं** में उपलब्ध है।

मिशन शक्ति के बारे में

- मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने हेतु मिशन मोड में संचालित एक प्रमुख योजना है।
- इसके अंतर्गत दो उप-योजनाएँ शामिल हैं— ‘संबल’ और ‘समर्थ्य’।
- **संबल उप-योजना:** यह महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित योजनाओं को संशोधनों सहित सम्मिलित किया गया है—
 - वन स्टॉप सेंटर (OSC)
 - महिला हेल्पलाइन (WHL)
 - बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP)
- इसके अतिरिक्त ‘नारी अदालत’ (महिला सामूहिक मंच) को एक नए घटक के रूप में जोड़ा गया है।

स्रोत: AIR

डार्क वेब

संदर्भ

- केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम अब “नए डार्क वेब” के रूप में विकसित हो गया है।

परिचय




- सरकार ने तर्क दिया कि टेलीग्राम की संरचना और गोपनीयता संबंधी विशेषताओं ने इसे साइबर अपराधियों, धोखाधड़ी नेटवर्कों, उग्रवादी एवं आतंकवादी संगठनों तथा परीक्षा प्रश्नपत्र लीक करने वाले समूहों के लिए एक पसंदीदा माध्यम बना दिया है।
- सरकार की दलीलें मुख्यतः **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)** के आकलन पर आधारित थीं, जिसमें टेलीग्राम को अवैध ऑनलाइन गतिविधियों का तीव्रता से उभरता केंद्र बताया गया है।

डार्क वेब क्या है?

- डार्क वेब इंटरनेट का वह भाग है, जहाँ उपयोगकर्ता **द ओनियन राउटर (Tor)** जैसे विशेष वेब ब्राउज़रों के माध्यम से अनुक्रमित वेब सामग्री तक गुमनाम रूप से पहुँच सकते हैं।

- **उत्पत्ति :** इसकी उत्पत्ति वर्ष 2002 में **अमेरिकी नौसेना अनुसंधान प्रयोगशाला** के शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के कार्यों से जुड़ी मानी जाती है।
- उन्होंने यह समझा कि डिजिटल गतिविधियों और संचार को कितनी आसानी से निगरानी, अवरोधन तथा दुरुपयोग का शिकार बनाया जा सकता है।
- इसी कारण खुफिया समुदाय के लिए अधिक सुरक्षित संचार माध्यम की आवश्यकता से डार्क वेब की अवधारणा विकसित हुई।
- **चिंताएँ :** डार्क वेब अनियमित है, अर्थात् इसका संचालन और संरक्षण विश्वभर में फैले व्यक्तियों के विशाल नेटवर्क द्वारा किया जाता है।
- यही परिचालन मॉडल इसे साइबर अपराधियों तथा संदिग्ध उद्देश्यों वाले अन्य व्यक्तियों के लिए अत्यंत उपयोगी और आकर्षक बनाता है।

ओपन वेब, डीप वेब और डार्क वेब में अंतर

<p>Surface Web</p> <p>The searchable part of the internet accessible through standard search engines.</p> <p>What's there: Blogs, forums, social media, news, etc.</p>	 <p>Accessibility: Open</p>
<p>Deep Web</p> <p>The unindexed and non-searchable part of the internet that includes private content.</p> <p>What's there: Company databases, subscription content, etc.</p>	 <p>Accessibility: Password-protected</p>
<p>Dark Web</p> <p>The hidden and anonymous part of the internet that isn't accessible through standard browsers.</p> <p>What's there: Hidden content, anonymous forums, etc.</p>	 <p>Accessibility: Requires Tor browser</p>

स्रोत: (TH)

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY)

संदर्भ

- प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के अंतर्गत ₹2,400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी।

PM-VBRY के बारे में

- यह वर्ष 2025 में प्रारंभ की गई केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है।
- इसका कार्यान्वयन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- उद्देश्य : रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देना।
 - रोजगारयोग्यता में वृद्धि करना।
 - सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना।
 - यह योजना देशभर में 3.5 करोड़ से अधिक सार्थक रोजगार अवसरों के सृजन का लक्ष्य रखती है।
- मुख्य विशेषताएँ : प्रथम बार रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को ₹15,000 तक का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
 - नियोक्ताओं के लिए सरकार प्रत्येक नए कर्मचारी के छह माह तक स्थायी रोजगार में बने रहने पर ₹3,000 तक का प्रोत्साहन देगी।
 - इस पहल से औपचारिक कार्यबल में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहन मिलने तथा दीर्घकालिक आर्थिक विकास को गति मिलने की अपेक्षा है।

स्रोत: TH

QS रैंकिंग 2027

संदर्भ

- हाल ही में QS (क्वाक्वेरेली साइमंड्स) विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 जारी की गई, जिसमें विश्वभर के उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन किया गया।

प्रमुख निष्कर्ष

- इस रैंकिंग में 106 देशों एवं क्षेत्रों के 1,500 से अधिक संस्थानों का मूल्यांकन किया गया।
- इसमें 52 भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान मिला है, जिससे भारत विश्व की पाँचवीं सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाली उच्च शिक्षा प्रणाली बन गया है।
- आईआईटी दिल्ली भारत का सर्वोच्च रैंक प्राप्त संस्थान बना हुआ है, जिसे वैश्विक स्तर पर 118वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।
- आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं।
- वैश्विक स्तर पर शीर्ष संस्थान:
 - मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT), अमेरिका – प्रथम स्थान (लगातार 15वें वर्ष)।
 - इंपीरियल कॉलेज लंदन, यूनाइटेड किंगडम – संयुक्त द्वितीय स्थान।
 - स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका – संयुक्त द्वितीय स्थान।
 - ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम – इसके बाद स्थान।
 - अन्य प्रमुख संस्थान—
 - पेकिंग विश्वविद्यालय (चीन) – 13वाँ स्थान।
 - टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख (जर्मनी) – 25वाँ स्थान।
- चिंताएँ : रिपोर्ट के अनुसार भारतीय विश्वविद्यालयों ने अनुसंधान प्रभाव और स्नातक रोजगारयोग्यता में उल्लेखनीय प्रगति की है।
 - इसके बावजूद वे अंतरराष्ट्रीय छात्रों एवं शिक्षकों को आकर्षित करने की चुनौती का सामना कर रहे हैं।

QS रैंकिंग के बारे में

- QS क्वाक्वेरेली साइमंड्स की स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है।
- यह संस्था अंतरराष्ट्रीय उच्च शिक्षा क्षेत्र को डेटा, शोध तथा परामर्श सेवाएँ प्रदान करने में विशेषज्ञता रखती है।

- **QS रैंकिंग**, जिसकी शुरुआत 2004 में हुई थी, वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंगों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित मानी जाती है और संस्थानों का निष्पक्ष मूल्यांकन प्रस्तुत करती है।
- **मूल्यांकन के प्रमुख संकेतक**: QS रैंकिंग संस्थानों का मूल्यांकन 10 प्रमुख मानकों के आधार पर करती है, जिनमें शामिल हैं—
 - शैक्षणिक प्रतिष्ठा
 - रोजगार परिणाम
 - अंतरराष्ट्रीय संकाय अनुपात
 - अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क
 - अंतरराष्ट्रीय छात्र विविधता
 - शिक्षक-छात्र अनुपात
 - सततता आदि।
- **पात्रता हेतु आय मानदंड**:
 - **EWS परिवार**: वार्षिक आय ₹3 लाख तक।
 - **LIG परिवार**: वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख तक।
 - **MIG परिवार**: वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹9 लाख तक।
- **लागत साझेदारी** : आवास निर्माण की लागत केंद्र सरकार, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) तथा लाभार्थियों के बीच साझा की जाती है।
 - विभिन्न क्षेत्रों में लागत साझेदारी का स्वरूप भिन्न-भिन्न हो सकता है।
- **उपलब्धियाँ**: PMAY-U तथा PMAY-U 2.0 के अंतर्गत संयुक्त रूप से देशभर में 1.27 करोड़ से अधिक आवासों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

स्रोत: AIR

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0

संदर्भ

- केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2.13 लाख से अधिक अतिरिक्त आवासों को स्वीकृति प्रदान की है।

PMAY-U के बारे में

- यह आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) की एक प्रमुख योजना है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा ₹2.50 लाख करोड़ तक की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
- इसे सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। यह 25 जून 2015 को प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) का उन्नत एवं विस्तारित संस्करण है।
- यह योजना उन परिवारों के लिए खुली है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) तथा मध्यम आय वर्ग (MIG) से संबंधित हैं और जिनके पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)

- **प्रारंभकर्ता**: ग्रामीण विकास मंत्रालय
- **पृष्ठभूमि**: इसे 1 अप्रैल 2016 को पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन करके प्रारंभ किया गया था।
 - इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को मूलभूत सुविधाओं सहित पक्के आवास
 - उपलब्ध कराना है।

स्रोत: AIR

अभ्यास खान क्वेस्ट 2026

संदर्भ

- अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 का आयोजन 20 जून से 3 जुलाई 2026 तक उलानबटार स्थित फाइव हिल्स प्रशिक्षण क्षेत्र में किया जाएगा।

परिचय

- इस अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुई थी।

- इसके पश्चात वर्ष 2006 से यह एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास के रूप में विकसित हो गया।
- वर्ष 2026 में इसका 23वाँ संस्करण आयोजित किया जा रहा है।
- **उद्देश्य:** संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत संचालित शांति समर्थन अभियानों में भाग लेने वाली सेनाओं के बीच परस्पर संचालन क्षमता तथा सहयोग को प्रोत्साहन देना।
- विभिन्न देशों की सैन्य टुकड़ियों के बीच समन्वय, अनुभव-साझाकरण तथा संयुक्त शांति स्थापना क्षमताओं को सुदृढ़ करना।

स्रोत: AIR



